

बजट 2022-23: प्रत्यक्ष कर

प्रलिस के लयः

प्रत्यक्ष कर से संबंढतऱ नयऱड, कारुडकरड, डुडनररुँ तथर सरकरर डवरर करऱ डर डदलरव ।

डेनुस के लयः

वृदुधररुँ वकररस, डडरवेरुी वकररस, संसरधनुँ कर संगुरहरण, सरकररी नीतरुीरुँ औरु हरसुतकरषेड, प्रत्यक्ष करुँ कर डहतुतुव ।

करुडर डेँ करुीरुँ?

हरल ही डेँ वतऱत डनुतुरी डवरर संसद डेँ केंदुरीड डजट 2022-23 डेश करऱ डर डर डेँ ।

- करुँ और करुतुवुी से संबंढतऱ डुरसुतररुँ कर उदुदेशुड कर डुरणरली कर सरल डनरनर, करदरतररुँ डवरर सुवैकुकुडर अनुडरलन कर डदुवर डेनर और करु से संबंढतऱ डुकदुडडेडररुी कर डड करनर डेँ ।
- प्रत्यक्ष कर डक डेसर कर डेँ डसऱकर डुगतरन डक वुडकुतुडर डरंगठन सीधे उस डकररुँ करुतर डेँ डसऱने डसे लगरर डर । उदरहरण: डरडकर, वरसुतुवकर संडतुतुकर, वुडकुतुडर संडतुतुकर डर संडतुतुडर डर कर ।



Extending Period of Incorporation by one more year of Eligible Startups for Providing Tax Incentives



Better Litigation Management to Avoid Repetitive Appeals



Income from Transfer of Virtual Assets to be Taxed at 30%



Surcharge/ Cess on Income & Profits Not Allowable as Business Expenditure

व्यक्तिविशेष के लिये:

- **अद्यतन वविरणी/अपडेटेड रटिर्न:**
 - सरकार ने दाखलि कयि गए आयकर रटिर्न (Income Tax Returns- ITRs) में चूक को ठीक करने के लिये वन-टाइम वडिओ (One-Time Window) की सुवधि प्रदान करने का प्रस्ताव कयि है।
 - करदाता संबंधित आकलन वर्ष के अंत से दो वर्षों के भीतर अद्यतन वविरणी/अपडेटेड रटिर्न (Updated Returns) फाइल कर सकते हैं।
- **दवियांगजनों को कर राहत:**
 - दवियांग आशरतियों को उनके माता-पति/अभभावकों के जीवनकाल के दौरान यानी माता-पति/अभभावकों के 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर भी बीमा योजनाओं से वार्षिकी और एकमुश्त राशिकी अदायगी की अनुमति प्रदान की गई है।
 - वर्तमान कानून माता-पति या अभभावक हेतु कटौती का प्रावधान केवल तभी करता है जब माता-पति या अभभावक की मृत्यु पर दवियांग व्यक्ति को एकमुश्त भुगतान या वार्षिकी (Annuity) उपलब्ध हो।
- **राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच समानता:**
 - राज्य सरकार के कर्मचारियों के **राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली** खाते में नयिकता के योगदान पर कर कटौती की सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।
 - इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान सुवधि प्रदान करने में मदद मिलेगी।
 - यह सामाजिक सुरक्षा लाभों को बढ़ाने में मदद करेगा।

कॉर्पोरेट व्यवसायों और सहकारी समितियों के लिये क्या है?

- **सहकारी समितियों के लिये वैकल्पिक न्यूनतम भुगतान कर और अधभार:**
 - **सहकारी समितियों** और कंपनियों को समान अवसर उपलब्ध कराने हेतु सहकारी समितियों के लिये वैकल्पिक न्यूनतम कर भुगतान को घटाकर 15 प्रतिशत कयि गया।
 - उन सहकारी समितियों के लिये अधभार की मौजूदा दर को **12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत** कयि गया, जिनकी कुल आमदनी **एक करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए तक** है।
 - इससे सहकारी समितियों तथा **इसके सदस्यों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी जो कजियादातर ग्रामीण एवं कृषक समुदायों से हैं।**
- **स्टार्टअप के लिये प्रोत्साहन:**
 - मार्च 2022 से पहले स्थापित **स्टार्टअप** को नगिमन की अवधि से दस वर्षों में से लगातार तीन वर्षों के लिये कर प्रोत्साहन प्रदान कयि गया था।
 - कोवडि महामारी को देखते हुए सरकार द्वारा इस तरह के कर प्रोत्साहन प्रदान करने के लिये पात्र स्टार्टअप के नगिमन की अवधि को एक और वर्ष यानी मार्च 2023 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

वर्चुअल डजिटल संपत्तियाँ:

- **वर्चुअल डजिटल परसंपत्तियों के कराधान हेतु योजना:**
 - वर्चुअल डजिटल परसंपत्तियों के लिये विशेष कर प्रणाली लागू की गई है। कसि भी वर्चुअल डजिटल परसंपत्तिके हस्तांतरण से होने वाली आय पर कर की दर 30 प्रतिशत होगी।
 - इस प्रकार की आय की गणना करते समय अधगिरहण लागत को छोड़कर कसि भी खर्च अथवा भत्ते के लिये कटौती नहीं होगी।
 - वर्चुअल डजिटल परसंपत्तिके हस्तांतरण से हुए नुकसान की भरपाई कसि अन्य आय से नहीं की जा सकती।
 - लेन-देन के वविरण हेतु वर्चुअल डजिटल परसंपत्तिके हस्तांतरण के संबंध में कयि गए भुगतान पर एक नश्चिति मौद्रिक सीमा से ऊपर की राशिके लिये 1 प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर कटौती (TDS) देय होगी।
 - वर्चुअल डजिटल परसंपत्तिके उपहार पर भी प्राप्तकर्ता द्वारा कर की राशि देय होगी।

कराधान को सरल बनाना:

- **मुकदमा प्रबंधन:**
 - यदि कसि मामले में कानून संबंधी उसी तरह का कोई वषिय शामिल हो, जसिसे संबंधित कोई मामला उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हो तो वभाग द्वारा अपील दायर करने की प्रक्रिया को न्यायालय द्वारा फैसला दिये जाने तक टाल दिये जाएगा।
 - करदाताओं और वभाग के बीच प्रक्रिया के दोहराव से बचने में इससे काफी मदद मिलेगी।
- **कर चोरी की रोकथाम:**
 - तलाशी एवं सर्वेक्षण कार्रवाइयों के दौरान पता लगी आय/राशिके संबंध में कसि भी प्रकार की हानिके प्रति समंजन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- **अंतरराष्ट्रीय ववित्तीय सेवा केंद्रों (IFSC) को कर प्रोत्साहन:**
 - नरिदषिट शर्तों के अधीन नमिनलखिति को कर से छूट दी जाएगी:
 - 'ऑफशोर डेरविटवि' उपकरणों से अनविसी की आय।
 - एक अपतटीय बैंकिंग इकाई द्वारा जारी कयि गए 'ओवर द काउंटर डेरविटवि' से आय।
 - रॉयल्टी से आय और जहाज़ को लीज़ पर देने से प्राप्त ब्याज।
 - IFSC में पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं से प्राप्त आय।

कर युक्तिकरण के सरकार के प्रयास:

- टीडीएस प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाना:
 - एजेंटों को कर योग्य व्यवसायों हेतु प्रोत्साहित करने संबंधी लाभ प्रदान करना।
 - वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे लाभों का कुल मूल्य 20,000 रुपए से अधिक होने पर लाभ देने वाले व्यक्तियों को कर कटौती प्रदान की जाती है।
- अधभार का युक्तिकरण:
 - एओपी (अनुबंध के नषिपादन के लिये गठित कंसोर्टियम) पर अधभार की उच्चतम सीमा 15 प्रतिशत निर्धारित की गई है।
 - व्यक्तिगत कंपनियों और एओपी के बीच अधभार में अंतर को कम किया गया है।
 - किसी भी प्रकार की परसिंपत्त के हस्तांतरण से होने वाले दीर्घावधि पूंजीगत लाभ पर अधभार की अधिकतम सीमा 15 प्रतिशत होगी।
 - इससे स्टार्टअप समुदाय को प्रोत्साहन मिलेगा।

स्रोत: पी.आई.बी.

बजट 2022-23: अप्रत्यक्ष कर

प्रलिस के लिये:

अप्रत्यक्ष कर, बजट, जीएसटी, विशेष आर्थिक क्षेत्र, मेक इन इंडिया।

मेन्स के लिये:

वशिवसनीय कर व्यवस्था।

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय बजट 2022-23 स्थिर और पूर्वानुमेय कर व्यवस्था की घोषित नीति को जारी रखते हुए अधिक सुधार लाने का इरादा रखता है जो एक वशिवसनीय कर व्यवस्था स्थापित करने के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएगा।

अप्रत्यक्ष कर एक ऐसा कर है जिससे वस्तुओं और सेवाओं पर उस ग्राहक तक पहुँचने से पहले अधिपति किया जाता है जो अंततः खरीदे गए सामान या सेवा के बाजार मूल्य के हिस्से के रूप में अप्रत्यक्ष कर का भुगतान करता है। उदाहरण के लिये वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), आयात शुल्क।

प्रमुख बडि

- **रकिॉर्ड जीएसटी संग्रह:** कोरोनावायरस महामारी के बावजूद जनवरी 2022 में जीएसटी संग्रह ने 1.40 लाख करोड़ रुपए के रकिॉर्ड को छुआ।
 - जीएसटी सहकारी संघवाद की भावना को प्रदर्शित करता है और 'एक बाजार-एक कर' के रूप में भारत के सपने को पूरा करता है।
- **विशेष आर्थिक क्षेत्र:** SEZs का सीमा शुल्क प्रशासन पूरी तरह से आईटी संचालित होगा और उच्च सुविधा एवं जोखिम-आधारित जाँच पर ध्यान देने के साथ सीमा शुल्क राष्ट्रीय पोर्टल पर कार्य करेगा।
- **सीमा शुल्क सुधार और शुल्क दर परिवर्तन:** सीमा शुल्क प्रक्रिया को पूर्णतः फेसलेस कर दिया गया है। सीमा शुल्क सुधारों ने नमिनलखित के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है:
 - घरेलू क्षमता निर्माण।
 - MSMEs को समान अवसर प्रदान करना।
 - कच्चे माल की आपूर्ति पक्ष की बाधाओं को कम करना।
 - व्यापार में सुगमता को बढ़ाना।
 - PLIs और चरणबद्ध वनरिमाण योजनाओं जैसी अन्य नीतितगत पहलों हेतु सक्रम होना।
- **परयोजना आयात और पूंजीगत सामान: राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति, 2016 का लक्ष्य वर्ष 2025 तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दोगुना करना है।**
 - इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे और परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी।
 - हालाँकि बजट, उर्वरक, कपड़ा, जूते, खाद्य प्रसंस्करण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिये पूंजीगत वस्तुओं के शुल्क में कई छूटें दी गई हैं, यहाँ तक कि कुछ मामलों में तीन दशकों से भी अधिक समय तक की छूट दी गई है।
 - इन छूटों ने घरेलू पूंजीगत वस्तु क्षेत्र के विकास में बाधा डाली है।
 - बजट में पूंजीगत वस्तुओं और परयोजना आयात में रियायती दरों को धीरे-धीरे समाप्त करने का प्रस्ताव है।
 - बजट में **7.5% का मध्यम टैरिफ लागू** करने का प्रावधान है जो घरेलू क्षेत्र तथा 'मेक इन इंडिया' के विकास के लिये अनुकूल होगा।

■ क्षेत्र-वशिष्ट प्रस्ताव:

- **इलेक्ट्रॉनिक्स:** पहनने योग्य उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक्स स्मार्ट मीटर के घरेलू निर्माण की सुविधा के लिये एक श्रेणीबद्ध दर संरचना प्रदान करने हेतु सीमा शुल्क दरों को संतुलित किया जाना है।
 - देश में कलाई में पहनने योग्य उपकरणों, सुनने योग्य उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक्स स्मार्ट मीटर के उत्पादन हेतु **एक चरणबद्ध वनिरिमाण कार्यक्रम (PMP)** की घोषणा की गई।
 - PMP शुरू में कम मूल्य के सामान के निर्माण को प्रोत्साहित करेगा और फिर उच्च मूल्य के घटक के निर्माण को बढ़ावा देगा।
- **रत्न और आभूषण:** कटिंग और पॉलिश किये गए हीरे और रत्नों पर सीमा शुल्क घटाकर 5% कर दिया गया है।
 - साधारण तरीके से कटे हुए हीरे पर सीमा शुल्क नहीं लगाया जाएगा।
- **एमएसएमई और नरियात:** भारत में निर्मित कृषिक्षेत्र के लिये उपकरणों तथा उन उपकरणों पर छूट को युक्तिसंगत किया जा रहा है।
 - इसके अलावा नरियात को प्रोत्साहित करने हेतु कई वस्तुओं पर छूट प्रदान की जा रही है।
- **ईंधन के सम्मिश्रण को प्रोत्साहित करने हेतु शुल्क:** ईंधन के सम्मिश्रण को प्रोत्साहित करने के लिये टैरिफि उपाय शुरू किए जाएंगे।
 - इस बीच ईंधन के सम्मिश्रण को और प्रोत्साहित करने हेतु 1 अक्टूबर, 2022 से गैर-मिश्रित ईंधन पर 2 रुपए/लीटर का अतिरिक्त अंतर उत्पाद शुल्क (Additional Differential Excise) लगेगा।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

बजट 2022 में आयात शुल्क में बदलाव

प्रलिमिंस के लिये:

एक स्टेशन एक उत्पाद, एक ज़िला एक उत्पाद (ODOP) योजना, आयात शुल्क।

मेन्स के लिये:

बजट 2022-23 में उत्पादों के आयात शुल्क में बदलाव का प्रभाव और इसका महत्त्व।

चर्चा में क्यों?

वित्तमंत्री ने वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में कई मदों पर सीमा शुल्क में बदलाव पेश किये हैं।

- इसका अर्थ यह है कि सीमा शुल्क में बदलाव के आधार पर आयात अधिक महंगा या सस्ता हो जाता है।

आयात शुल्क परिवर्तन:

- 'छाते' पर सीमा शुल्क को दोगुना बढ़ाकर 20% कर दिया गया, जबकि छतरियों के पुरजों के आयात पर दी गई छूट को वापस ले लिया गया।
- इसी तरह सगिल या मल्टीपल लाउडस्पीकरों पर सीमा शुल्क को 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है।
- कटे और पॉलिश किये गए हीरे, हींग, कोको बीन्स, मथाइल अल्कोहल तथा एसटिक एसिड पर आयात शुल्क कम किया गया है।
- पूंजीगत वस्तुओं और परियोजना आयात पर शुल्क की रियायती दरों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर और 7.5% का एक मध्यम टैरिफि लागू करके युक्तिसंगत बनाया गया।
 - **प्रोजेक्ट आयात योजना** के तहत एक कंपनी द्वारा आयात किये गए सामान को सीमा शुल्क टैरिफि अधिनियम, 1975 में एक ही टैरिफि के तहत रखा जाता है, ताकि भाल के तेज़ी से मूल्यांकन और निकासी की सुविधा सुनिश्चित हो सके।
 - वित्त वधियक 2022-23 के अनुसार, टैरिफि परिवर्तन 1 मई, 2022 से प्रभावी होंगे।

आयात शुल्क बढ़ाने के पीछे कारण:

- **घरेलू उद्योगों की सुरक्षा हेतु:**
 - छतरियों जैसी वस्तुओं के लिये आयात शुल्क में वृद्धि पिछले वर्ष खलौनों पर आयात शुल्क में वृद्धि के अनुरूप है।
 - बढ़ोतरी उन उद्योगों के लिये की जा रही है, जो किसी भी बड़ी तकनीक से निर्मित वस्तुओं का निर्माण नहीं करते हैं।
 - उदाहरण के लिये छतरियों का निर्माण 10-12 ज़िलों में फैली छोटी इकाइयों में किया जाता है, जिसमें केरल प्रमुख वनिरिमाण राज्य है।
 - सरकार ऐसे उद्योगों को संरक्षण देने के पक्ष में है।
- **'एक स्टेशन-एक उत्पाद' को लोकप्रिय बनाना:**

- यह बजट 2022 में घोषित स्थानीय व्यवसायों और आपूर्ति शृंखलाओं को लोकप्रिय बनाने के लिये एक स्टेशन-एक उत्पाद को बढ़ावा देने के अनुरूप है।
- एक अवधारणा के रूप में एक स्टेशन-एक उत्पाद का उद्देश्य उस क्षेत्र के रेलवे स्टेशन को उत्पाद हेतु प्रचार और बिक्री केंद्र बनाकर भारतीय रेलवे के प्रत्येक स्टॉप से एक स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देना है।
- 'एक स्टेशन-एक उत्पाद' की अवधारणा '[एक ज़िला एक उत्पाद योजना](#)' पर आधारित है। एक ज़िले की क्षमताओं के आधार पर ओडीओपी एक ज़िले की वास्तविक क्षमता को साकार करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, रोजगार उत्पन्न करने और ग्रामीण उद्यमिता की दृष्टि में एक परिवर्तनकारी कदम रहा है।

हाल के वर्षों में आयात शुल्क में बदलाव:

- वर्ष 2021 में स्टील स्करैप उद्योग को सीमा शुल्क में छूट प्रदान की गई जैसी अब एक और वर्ष के लिये बढ़ा दिया गया है।
 - इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तर के द्वितीयक इस्पात उत्पादकों को राहत मिलने की संभावना है।
- पछिल्ले पाँच वर्षों में कई अवसरों पर आयात शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। घरेलू उद्योग के विकास तथा पोषण के उद्देश्य से **सेलफोन के पुरजों एवं सौर पैनलों** जैसी अन्य वस्तुओं में सबसे न्यमित बढ़ोतरी देखी गई है।
- **गैर-कृषि उत्पादों पर भारत का सीमा शुल्क** बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी से पहले वर्ष 1991-92 में सामान्य दरों से 150%, वर्ष 1997-98 में 40%, वर्ष 2004-05 में 20% तथा **2007-08 में 10% तक कम** हो गया था।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

फलीपींस को ब्रह्मोस का नरियात

प्रलमिस के लिये:

ब्रह्मोस मिसाइल, दक्षिण चीन सागर।

मेन्स के लिये:

रक्षा प्रौद्योगिकी, रक्षा नरियात।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में फलीपींस ने **ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल** के तट आधारित एंटी-शिप संस्करण की आपूर्ति के लिये **ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड** के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। यह इस मिसाइल के लिये पहला नरियात ऑर्डर है, जो भारत और रूस का संयुक्त उत्पाद है।

- **दक्षिण चीन सागर** में विवादित द्वीपों को लेकर चीन के साथ तनाव के बीच फलीपींस इस मिसाइल को शामिल करना चाहता है।
- कई देशों ने ब्रह्मोस मिसाइल हासिल करने में दिलचस्पी दिखाई है। उदाहरण के लिये इंडोनेशिया और थाईलैंड के साथ चर्चा उन्नत चरणों में है।

ब्रह्मोस मिसाइल की विशेषताएँ:

- ब्रह्मोस **रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन** (The Defence Research and Development Organisation) तथा रूस के NPOM का एक संयुक्त उद्यम है।
 - इसका नाम भारत की **ब्रह्मपुत्र नदी** और रूस की मोस्क्वा नदी के नाम पर रखा गया है।
- यह दो चरणों वाली (पहले चरण में ठोस प्रणोदक इंजन और दूसरे में तरल रैमजेट) मिसाइल है।
- यह एक मल्टीप्लेटफॉर्म मिसाइल है यानी इसे ज़मीन, हवा और समुद्र तथा बहु क्षमता वाली मिसाइल से सटीकता के साथ लॉन्च किया जा सकता है, जो किसी भी मौसम में दिन और रात में काम करती है।
- यह **'फायर एंड फॉरगेट्स'** सिद्धांत पर कार्य करती है यानी लॉन्च के बाद इसे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती।
- ब्रह्मोस सबसे तेज़ क्रूज़ मिसाइलों में से एक है, यह वर्तमान में मैक 2.8 की गति के साथ कार्य करती है, जो कविवर्तन की गति से लगभग 3 गुना अधिक है।
- हाल ही में **ब्रह्मोस के एक उन्नत संस्करण** (वसितारति रेंज सी-टू-सी वेरिएंट) का परीक्षण किया गया था।
 - भारत द्वारा जून 2016 में **मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (Missile Technology Control Regime-MTCR)** में शामिल होने बाद इसकी रेंज को अगले चरण में 450 कमी. तथा 600 कमी. तक वसितारति करने की योजना है।
 - ब्रह्मोस मिसाइल को शुरुआत में **290 कमी. की रेंज** के साथ विकसित किया गया था।

मसिाइल प्रौद्योगिकी नरिंतरण वरवसुथल (MTCR) कुरल है?

- यह मसिाइल और मलनव रहति हवई वलहन प्रौद्योगिकी के प्रसर को रोकने हेतु 35 देशों के बीच एक अनौपचलरकल एवं सुवैचुछकल सलझेदलरी है, जो 500 कललगुरल से अधकल पेलोड को 300. से अधकल दूरी तक ले खने में सकुषम है ।
- उन सदसुथों को ऐसी मसिाइलों और यूएवी प्रणललथियों की आपूरत करणे से रोकल खलतल है जो गैर-सदसुथों की एमटीसीआर दवलरल नरिंतरतल हेते हैं ।
- ये नरिणय सभल सदसुथों की सहमतल से लयल खलते हैं ।
- यह सदसुथ देशों कल एक गैर-संधलसंध है, खसलमें मसिाइल प्रणललथियों हेतु सूचना सलझे करणे, रलषुटुरीय नरिंतरण कलनूनों और नरलखल नीतथियों तथल इन मसिाइल प्रणललथियों की ऐसी महतुतुवपूरण प्रौद्योगिकलथियों के हसुतलंतरण को सीमतल करणे के लयल एक नयलम-आधलरतल वनलथलमन तंतर के बलरे में कुछ दशल-नरलदेश हैं ।
- इसकी सुथलपनल अपुरैल 1987 में G-7 देशों- यूएसए, यूके, फुरलंस, खरुमनी, कनलडल, इटली और खलपलन दवलरल की गई थी ।

भलरत के रकुषल नरलखल की सुथतल कुरल है?

- रकुषल उतुपलदन में आतुमनरलभरतल प्रलपुत करणे के लयल रकुषल नरलखल सरकलर के अभयलन कल एक सुतंभ है ।
- 30 से अधकल भलरतीय रकुषल कंपनलथियों ने इटली, मललदीव, शुरीलंकल, रूस, फुरलंस, नेपाल, मलरलशस, इखुरलखल, मसलर, संयुकुत अरब अमीरलत, भूटलन, इथलथलपथल, सऊदी अरब, फललीपीस, पोलैंड, कलली और स्पेन आदल देशों को हथथलरों एवं उपकुरणों कल नरलखल कथल है ।
- नरलखल में वुतुकुतगतल सुरकुषल उपकुरणों, रकुषल इलेकुरऑनकलस ससलुतुम, इंखीनयलरगल यलंतुरकल उपकुरण, अपतटीय गशुती खलखल, उनुनत हलुके हेलीकऑपुटर, एवथलनकलस सुुट, रेडयलल ससलुतुम एवं रडलर ससलुतुम शलमलल हैं ।
- हलललंकल भलरत कल रकुषल नरलखल अभी भी अपेकुषतल सीमल तक नही पहुँखल है ।
 - सुुऑकहोम इंटरनेशनल पीस रसलरुख इंसुुटीटुुट (SIPRI) ने वरुष 2015-2019 के लयल प्रमुख हथथलर नरलखलतकों की सूची में भलरत को 23वें सुथलन पर ररखल है ।
 - भलरत अभी भी वैशुवकल हथथलरों कल केवल 0.17% हसलसल नरलखल करतल है ।
- रकुषल नरलखल में भलरत के नरलशलखनक प्रदरुशन कल कलरण यह है कल भलरत के रकुषल मंतुरलखल के पलस अब तक नरलखल हेतु कोई सडरुपतल एजेसी नही है ।
 - नरलखल कल वषलथ अलग-अलग नलगलमें पर छुडे दथल खलतल है, खेसे- 'बुरहडुस' यल 'रकुषल सलरुवखनकल शपलयरुड' और अनुय उपकुरम ।
- इस संदरुभ में KPMG रपलरुट 'डलफलंस एकुसडुऑरुस: अनटैपुड डुऑरेशलल' शलरुषक से एक वलशष "डलफलंस एकुसडुऑरुट हेल्प डेसुक" की सुथलपनल के पहले कुरण की सफलरलशल की गई है ।
 - रपलरुट में कलहल गलल है कल हेल्प-डेसुक से मलल इनडुऑरु के आधलर पर भलरतीय कंपनलथियों नरलखल हेतु सरकलरी मशीनरी के सलथ कलम कर सकुती हैं ।
- यदल भलरत डुऑरुस के देशों को बडुी सैनय प्रणलली प्रदलन करणे में सफल हेतल है, तो यह न केवल रकुषल नरलखल को बडुवल देगल, बलुकल खीन के प्रभलव कल डुकलबलल करणे के लयल एक रणनीतकल कदडु भी हेगल, कुरुंयकल वलह डलकसलतलन, बलंगुलदेश और डुरुयलडलर सहलतल एशथल में कई देशों को रकुषल उतुपलद प्रदलन करतल है ।

सुरुत: द हदुदु

UNSC में भलरत-रूस सहयुग

प्रलललस के लयल:

संयुकुत रलषुटुर सुरकुषल डरषलद, मसलक सडडुओतल, नलरडुडुी प्रकुरथल, शंडलई सहयुग संगठन, G20, नुु डेवलडडुऑरु डुकु (NDB) ।

डेनुस के लयल:

UNSC के कलमकलख से जुडे डुदुदे, संयुकुत रलषुटुर सुरकुषल डरषलद में सुधलर की आवशुयकतल, संयुकुत रलषुटुर और बहुडकषुथीय डुऑरु में भलरत-रूस सहयुग कल महतुतुव, भलरत-रूस संडुंध, रूस-युकुरेन तनलव पर भलरत कल रुख ।

कुरल में कुरुंय?

हलल ही में भलरत और रूस के बीच नई दललली में संयुकुत रलषुटुर से संडुंधतल डुदुदुओं पर दवडकषुथीय डरलडरुश वलरुतल आडुओखतल की गई ।

- रूस फरवरी, 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा।
- यह चर्चा 'नाटो' द्वारा पूर्व की ओर संभावित वसतिार को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच तनाव की पृष्ठभूमि में हुई।
- इससे पहले 21वाँ भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था, जिसमें भारत के वरिष्ठ और रक्षा मंत्रियों की उनके रूसी समकक्षों के साथ पहली '2+2 मंत्रसित्रीय वार्ता' भी शामिल थी।



संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय मंचों में सहयोग का क्या महत्त्व है?

- दोनों पक्षों ने विश्व मामलों में संयुक्त राष्ट्र द्वारा नभार्ई गई केंद्रीय समन्वय की भूमिका के साथ बहुपक्षवाद को फरि से मज़बूत करने के महत्त्व पर वशिष बल दया।
 - रूस ने दो वर्ष के कार्यकाल के लयि भारी बहुमत के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में भारत के चुनाव का स्वागत कया।
 - रूस एक सुधारति संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और परमाणु आपूरतकिर्रता समूह की स्थायी सदस्यता के लयि भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करता है।
- दोनों पक्ष समकालीन वैश्विक वास्तवकिताओं को परतबिबिति करने और अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के मुद्दों से नपिटने में इसे अधिक परतनिधित्व, परभावी और कुशल बनाने हेतु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के व्यापक सुधार का समर्थन करते हैं।
- दोनों पक्ष **BRICS** के भीतर सहयोग बढ़ाने हेतु परतबिदध हैं।
 - रूस ने 9 सतिंबर, 2021 को XIII **ब्रिक्स शिखर सम्मेलन** की मेज़बानी और नई **दिल्ली घोषणा** को अपनाने सहति 2021 में ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता पर भारत को बधाई दी।
- **नयु डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी)** की भूमिका को दोनों पक्षों द्वारा कोवडि-19 महामारी के स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभाव सहति वकिस चुनौतियों को संबोधति करने के लयि महत्त्वपूर्ण माना जाता है और एनडीबी को अधिक सामाजकि बुनयादी ढाँचा परयोजनाओं, डजिटल प्रौद्योगकियों के वतितपोषण की संभावना का पता लगाने हेतु प्रोत्साहति कया जाता है।
- भारत और रूस अपने संचालन के पछिले दो दशकों में **शंघाई सहयोग संगठन (SCO)** की उपलब्धियों को पहचानते हैं और मानते हैं कि इसमें एससीओ (SCO) सदस्य देशों के बीच आगे की बातचीत की काफी संभावनाएँ हैं।
- वे वशिष रूप से एससीओ की कषेत्रीय आतंकवाद वरिधी संरचना की कार्यक्षमता में सुधार करके **आतंकवाद**, उग्रवाद, **मादक पदार्थों की तसकरी**, सीमा पार संगठति अपराध और सूचना सुरक्षा खतरों का मुकाबला करने की परभावशीलता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रति करने का इरादा रखते हैं।
- वे वर्ष 2023 में **G-20** की भारत की अध्यक्षता को ध्यान में रखते हुए वैश्विक और पारस्परकि हति के मुद्दों पर G-20 प्रारूप एवं तीव्रता के साथ सहयोग करने के लयि भी दृढ़ हैं।
- दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कयिह हमारे महासागरों, सूचना और बाह्य अंतरकिष सहति वैश्विक साझाकरतताओं की सुरक्षा, पारदर्शति तथा अंतरराष्ट्रीय कानून को बनाए रखने के सदिधांतों पर आधारति होनी चाहयि।

रूस-यूक्रेन तनाव पर UNSC में भारत का रुख:

- यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की बैठक में भारत ने सभी के सुरक्षा हतियों को ध्यान में रखते हुए स्थितिको तत्काल नयित्तरति करने का भी आह्वान कया।
- भारत ने शांत कूटनीति और रूस-यूक्रेन तनाव के शांतपूरण समाधान का आह्वान कया।
 - "शांत कूटनीति" एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के व्यवहार को वचारशील वार्ता या कार्यो के माध्यम से परभावति करने के परयासों को संदर्भति करती है।

- भारत उन तीन देशों में से एक था (केन्या एवं गैबॉन अन्य दो देश थे) जसिने यूक्रेन पर चर्चा की जाएगी या नहीं, इस पर कार्यवधिकि मतदान से स्वयं को अलग रखा था।
 - अमेरिका ने बैठक प्रारंभ की और नौ अन्य देशों ने इस वार्ता को आयोजति करने के लयि मतदान कयि।
- भारत ने **जुलाई 2020 के युद्धवशिम**, वर्ष 2014 के **मसिक समझौते और नॉरमेंडी प्रकरयि** के लयि अपना समर्थन दोहराय।
 - नॉरमेंडी प्रकरयि रूस, यूक्रेन, जर्मनी और फ्रांस के बीच हुई वार्ताओं को संदरभति करती है, जो कविरष 2014 से प्रारंभ हुई, जब रूस ने करीमयि पर कब्जा कर लयि था।
- भारत ने **शांत कूटनीतिका** भी आहवान कयि क्योक अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देश और रूस सार्वजनकि रूप से कठोर रुख अपना रहे हैं।
 - भारत यूक्रेन में रह रहे छात्रों सहति 20,000 से अधिक भारतीय नागरकिों की सुरक्षा को लेकर चतिति है।

आगे की राह

- युद्ध की कसिी भी आशंका को खतम करने के लयि भारत समेत उन तमाम देशों को आगे आना चाहयि, जो दुनयि में शांतिकी स्थापना के लयि अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहे हैं।
- अपने संबंधों के पुनरुदधार की शुरुआत करने के लयि भारत और रूस व्यापक आर्थकि सहयोग हेतु एक स्पष्ट मार्ग बनाने और भारत-प्रशांत पर एक-दूसरे की अनविरयता की बेहतर समझ पैदा करने पर ध्यान केंदरति करेंगे।

स्रोत: द हट्टि

आभासी डजिटिल परसिंपत्तिका

प्रलिमिस के लयि:

आभासी डजिटिल परसिंपत्तिका, धारा (47A), डजिटिल रुपया, क्रपिटोकरेंसी।

मेन्स के लयि:

क्रपिटो करेंसी का वनियमन।

चर्चा में क्यो?

हाल ही में वतित मंत्री ने **बजट 2022** में **आभासी डजिटिल परसिंपत्तिका** से होने वाली आय पर **30% कर** की घोषणा की।

- इसके अतरकि एक मोदरकि सीमा से ऊपर 1% पर आभासी डजिटिल परसिंपत्तिका के हस्तांतरण के संबंध में कयि गए भुगतान पस्स्रोत पर कर कटौती (Tax Deduction at Source) का भी प्रस्ताव रखा गया है।

प्रमुख बट्टि

स्रोत पर कर कटौती:

- एक व्यक्तिका जो कसिी अन्य व्यक्तिका को नरिदषिट प्रकृतिका भुगतान करने हेतु उत्तरदायी है, उसके स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी तथा इस कटौती को केंदर सरकार के खाते में प्रेषति करना होगा।

आभासी डजिटिल संपत्तिका:

- वतित वधियक ने एक नया खंड (47A) दर्ज करके "आभासी डजिटिल परसिंपत्तिका" शब्द को परभिशति कयि।
- प्रस्तावति नए खंड के अनुसार, एक आभासी डजिटिल संपत्तिका अर्थ क्रपिटोग्राफकि माध्यमों से कसिी भी जानकारी, कोड, संख्या या टोकन (न तो भारतीय मुद्रा में या न कसिी वदिशी मुद्रा में) उत्पन्न करना है।

कराधान के पीछे क्यो तरक है?

- आभासी डजिटिल संपत्तिका ने हाल के दनों में अत्यधिक लोकप्रयिता हासलि की है और ऐसी डजिटिल संपत्तिकाओं की ट्रेडिंग की मात्रा में काफी वृद्धि

हुई है।

- इसके अलावा एक ऐसा बाज़ार उभर रहा है, जहाँ एक आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण हेतु भुगतान ऐसी किसी अन्य संपत्ति के माध्यम से किया जा सकता है।
- इन कारकों ने एक विशिष्ट कर व्यवस्था का निर्माण करना अनिवार्य बना दिया है।

आभासी डिजिटल परिसंपत्ति डिजिटल करेंसी से किस प्रकार अलग हैं?

- एक मुद्रा केवल तब मुद्रा कहलाती है, जब इसे केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता है, भले ही वह क्रिप्टो ही क्यों न हो।
 - हालाँकि जो कुछ भी इस परिभाषा के दायरे से बाहर है, उसे प्रायः क्रिप्टोकॉर्सेंसी के रूप में संदर्भित किया जाता है, लेकिन वे मुद्राएँ नहीं होती हैं।
 - इन्हें आभासी डिजिटल संपत्ति के रूप में भी संदर्भित किया जा सकता है।
 - आभासी डिजिटल परिसंपत्ति/विरच्युअल डिजिटल एसेट्स में नॉन-फंगबिल टोकन (Non-fungible tokens- NFTs) भी शामिल हैं जो एक ब्लॉकचेन पर यूनिक आईडेंटिफिकेशन कोड और मेटाडेटा के साथ क्रिप्टोग्राफिक एसेट्स हैं तथा उन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं। NFT का उपयोग व्यक्तियों की पहचान, संपत्ति के अधिकार आदि के लिये भी किया जा सकता है।
 - यह क्रिप्टो करेंसी जैसे वैकल्पिक टोकन से भिन्न है, अतः वाणिज्यिक लेन-देन के लिये एक माध्यम के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है।
- वित्त मंत्री द्वारा इस बात को स्पष्ट किया गया है कि RBI अगले वित्त वर्ष में डिजिटल मुद्रा (Digital Currency) जारी करेगा।
 - इसे डिजिटल रुपया (Digital Rupee) कहा जाएगा।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/news-analysis/03-02-2022/print>

